15
अध्याय

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1. भारत–अमेरिका सहयोग

भारत सीएमएम / सीबीएम क्लीअरिंग हाऊसः सीएमपीडीआई, रांची में 17 नवंबर, 2008 से कोयला मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी (यूएस ईपीए) के तत्वावधान में एक सीएमएम/सीबीएम क्लीअरिंग हाऊस कार्यशील है। इस संबंध में वाशिंगटन डीसी में यूएस ईपीए के मुख्यालय में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच दिनांक 16 नवंबर, 2006 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि पूरी हो जाने पर अगले प्रत्येक तीन वर्षों की अवधि के लिए इसका तीन बार विस्तार किया गया था। यूएस ईपीए ने अतिरिक्त तीन वर्षों अर्थात् 2018–21 के लिए 2018 में अनुदान सहायता का और विस्तार किया था। क्लीअरिंग हाउस की वेबसाइट http://www.cmmclearinghouse.cmpdi.co.in है।

वर्ष 2008, 2013, 2017, 2019 और 2020 में कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में यूएसईपीए–जीएमआई और सीएमपीडीआई–सीआईएल द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/वेबिनार का आयोजन किया गया था।

भारत को 2021–23 की अवधि के लिए ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव (जीएमआई) स्टीयरिंग कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। श्री वी.के. तिवारी, अपर सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार और श्री मनोज कुमार, सीएमडी, सीएमपीडीआई को जीएमआई की स्टीयरिंग कमेटी के लिए देश के प्रतिनिधियों के रूप में नामित किया गया है।

2. भारत–ऑस्ट्रेलियन सहयोग

वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआई ने 12 जून, 2013 को कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (सीएसआईआरओ) के साथ पांच वर्षों की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस एमओयू का अगले दस वर्षों के लिए नवीकरण कर दिया गया है जिस पर ब्रिसबेन (ऑस्ट्रेलिया) में 16 नवम्बर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे और भारत के माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में 22 नवम्बर, 2018 को आदान–प्रदान किया गया था ताकि साझा हित के क्षेत्रों में आदान–प्रदान और सहयोग संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जा सके तथा दोनों संगठनों को लाभ मिल सके।

चल रही अनुसंधान परियोजनाओं की स्थितिः

क. सीआईएल के कमान क्षेत्रों के भीतर सीएमएम स्रोत के निष्कर्षण हेतु क्षमता निर्माणः

कोयला मंत्रालय के एसएंडटी वित्तीय पोषण के अंतर्गत ''सीआईएल के कमान क्षेत्रों के भीतर सीएमएम स्रोत के निष्कर्षण हेतु क्षमता निर्माण'' नामक एसएंडटी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसे सीएमपीडीआई और सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया गया है। परियोजना की लागत 23.92 करोड़ रूपए है। परियोजना के निष्पादन के लिए सीएसआईआरओ और सीएमपीडीआई के बीच 22 दिसम्बर, 2016 को सहयोगात्मक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संशोधित परियोजना को पूरा करने की नियत समय सीमा 22 जून, 2022 है।

ख. कोयला खानों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए वर्चुअल रियलिटी माइन सिम्युलेटर (वीआरएमएस) का विकासः

सीआईएल के आरएंडडी वित्त पोषण के अंतर्गत इस परियोजना को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा सितम्बर, 2017 में अनुमोदन दिया गया था जिसे संयुक्त रूप से आईआईटी–आईएसएम (धनबाद), सीएमपीडीआई, ईसीएल, एनसीएल और सिमटार्स, ऑस्ट्रेलिया द्वारा कार्यान्वित किया गया है। परियोजना की लागत 14.10 करोड़ रूपए है।

सिमटार्स ने क्वींसलैंड सरकार के नीतिगत विचार–विमर्श में बदलाव के कारण परियोजना को पूरा करने में असमर्थता व्यक्त की, हालांकि दोनों परियोजनाएं अग्रिम चरण में हैं। कई पत्राचार के बाद, सिमटार्स ने सूचित किया कि यूक्यू एसएमआई–जेकेटेक, ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल रियलिटी माइन सिम्युलेटर (वीआरएमएस) से संबंधित परियोजना से जुड़ना

चाहता है। दिनांक 30.12.2020 को आयोजित सीआईएल के आर एंड डी बोर्ड की शीर्ष समिति की 32वीं बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी। सीआईएल के आर एंड डी बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित परियोजना को पूरा करने की नियत समयसीमा मई, 2022 है।

ग. जोखिम आधारित खान इमरजेंसी निकासी और रि–एंट्री प्रोटोकोल पर आधारित जोखिम को शामिल करते हुए भारतीय कोयले का जोखिम आकलन और विस्फोटकता के निर्धारण द्वारा विस्फोट को रोकने और इसके शमन के लिए दिशा–निर्देश तैयार करना:

सीआईएल के आरएंडडी वित्त पोषण के अंतर्गत इस परियोजना को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा अप्रैल, 2016 में अनुमोदन दिया गया था जिसे संयुक्त रूप से आईआईटी–आईएसएम (धनबाद), सीआईएमएफआर, सीआईएल, कोलकाता और सिमटार्स, ऑस्ट्रेलिया द्वारा कार्यान्वित किया गया है। परियोजना की लागत 24.13 करोड़ रूपए है।

ऑस्ट्रेलिया में नीतिगत विचार–विमर्श में बदलाव के कारण सिमटार्स ने 30 एम प्रोपगेशन ट्यूब की आपूर्ति और इंस्टालेशन में अपनी अक्षमता व्यक्त की। सिमटार्स, ऑस्ट्रेलियन कान्सलट जनरल (कोलकाता), ऑस्ट्रेड ट्रेड कमिश्नर (चेन्नई), क्वीन्सलैंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमिश्नर और कार्यकारी निदेशक, डीएनआरएमई, क्वीन्सलैंड सरकार और न्यूकासल विश्वविद्यालय का न्यूकासल इंस्टिट्यूट ऑफ एनर्जी रिसर्च (एनआईईआर) के साथ इस मामले पर बातचीत के पश्चात यह सामने आया कि एनआईईआर विस्तारित समय सीमा के भीतर असाइनमेंट को पूरा करने के लिए सीआईएमएफआर और आईएसएम के साथ सहयोग करने को तैयार है। एनआईईआर को परियोजना की अतिरिक्त उप–कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव को सीआईएल के आर एंड डी बोर्ड ने 03.09.2021 को आयोजित अपनी 31 वीं बैठक में अनुमोदन दिया है। सीआईएल के आर एंड डी बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित परियोजना को पूरा करने की समयसीमा अप्रैल, 2023 है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच "कोयला और खान" पर पहली संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की बैठक वर्चुअल रूप से 23 सितंबर, 2021 को कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसकी सह–अध्यक्षता श्री विनोद कुमार तिवारी, अपर सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत और ऑस्ट्रेलिया की ओर से संसाधन प्रभाग के प्रमुख श्री पॉल ट्रॉटमैन द्वारा की गई थी।

भारत–ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) के तहत अंतरिम करार को जल्द से जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बातचीत चल रही है।

3. एससीसीएल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

ओबी डम्प्स और गहरी ओसी खानों का स्थिरता विश्लेषण और डिजाइन ऑप्टीमाइजेशन के लिए सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त अनुसंधान परियोजना 25.11.2020 को पहले ही बंद कर दी गई थी क्योंकि सीएसआईआरओ से अपेक्षित प्रौद्योगिकी पहले ही प्राप्त कर ली गई थी।

माइन एडवाइस पीटीवाई. लिमिलेड (रसेल फ्रिथ)– आस्ट्रेलिया अद्रियाला शाफ्ट परियोजना में नई पीढ़ी की लोंगवॉल तकनीक के क्रियान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन कर रही है और निगरानी रख रही है।

4. एनएलसीआईएल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

देश में कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उन्नत कोयला उत्पादक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विचार किया गया है ताकि कोयला उद्योग, कौशल विकास तथा प्रशिक्षण आदि में कुशल प्रबंधन के लिए भूमिगत और ओपनकास्ट क्षेत्रों दोनों में नई प्रौद्योगिकी लाई जा सके। उपर्युक्त को देखते हुए, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, रूस, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जापान और चीन के साथ कोयला/लिग्नाइट संबंधी संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया था। अन्य बातों के साथ–साथ प्राथमिकता क्षेत्रों में आधुनिक भूमिगत प्रौद्योगिकी प्राप्त करना, हाई प्रोडक्टिव ओपनकास्ट खनन तकनीक लाना, कठिन भूगर्भीय दशाओं में भूमिगत जाकर काम करना, आग पर नियंत्रण तथा खान सुरक्षा शामिल है।

भारतीय कार्मिकों का प्रशिक्षण के साथ–साथ प्रौद्योगिकी का समावेश करना एक महत्वपूर्ण विचार है। इस संबंध में एनएलसी इंडिया लिमिटेड एनएलसीआईएल खानों में कम्पोजिट वैल्यूबल्ज लिग्नाइट उत्पादित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग कर रही है।